एक दशक की हिसाब किताब!

टैक्स

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों की सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही का विचार रही है। मीडिया में विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी अतिशयोक्ति सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देती है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावा

अपने 2019 घोषणापत्र में, भाजपा सरकार ने अनुपालन में सुधार और **टैक्स आधार में वृद्धि का आश्वासन दिया, टैक्स-जीडीपी अनुपात 12% तक पहुंच गया है, जो 2013-14 में 10.1%** था। "इस बढ़े हुए राजस्व को गरीबों के लाभ और अभूतपूर्व स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए तैनात किया गया है। हम अपनी नीति को इसी तरह जारी रखेंगे -टैक्स की दर को कम करना जिससे ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और अनुपालन में सुधार होगा क्योंकि हमारा आर्थिक मॉडल उद्यमिता और नवाचार पर आधारित है। "

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अनुमान लगाया था कि **जीएसटी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर आधार पर 2-2.5% की वृद्धि होगी।**

जीएसटी के तहत सभी अप्रत्यक्ष करों को एक साथ जोड़कर, "व्यवसाय करने में आसानी" से दक्षता में वृद्धि होगी, **जिससे कीमतों में कमी आएगी**।

वास्तविकता

प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर

- **प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर:** RBI के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अंतर 2009-10 में लगभग -2% था, जो वित्त वर्ष 2022 में -5% तक बढ़ गया है। इससे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर बढ़ गया है, जिससे वंचित वर्गों पर बोझ बढ़ गया है, पिछले कुछ वर्षों में संपन्न वर्गों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

- FY13-22 के बीच, देश के लिए प्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर का अनुपात 37:63 था, जो OECD देशों के अनुपात के लगभग **विपरीत** है।

- **कर-जीडीपी अनुपात:** भारत का कर-जीडीपी अनुपात हाल के वर्षों में बराबर से नीचे रहा है, जो वित्त वर्ष 2008 में 17.9% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। नतीजतन, कर-जीडीपी अनुपात 2013-14 में 10.1 प्रतिशत से केवल 1.6% प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 11.7 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त वर्ष 2008 की तुलना में अभी भी कम है।

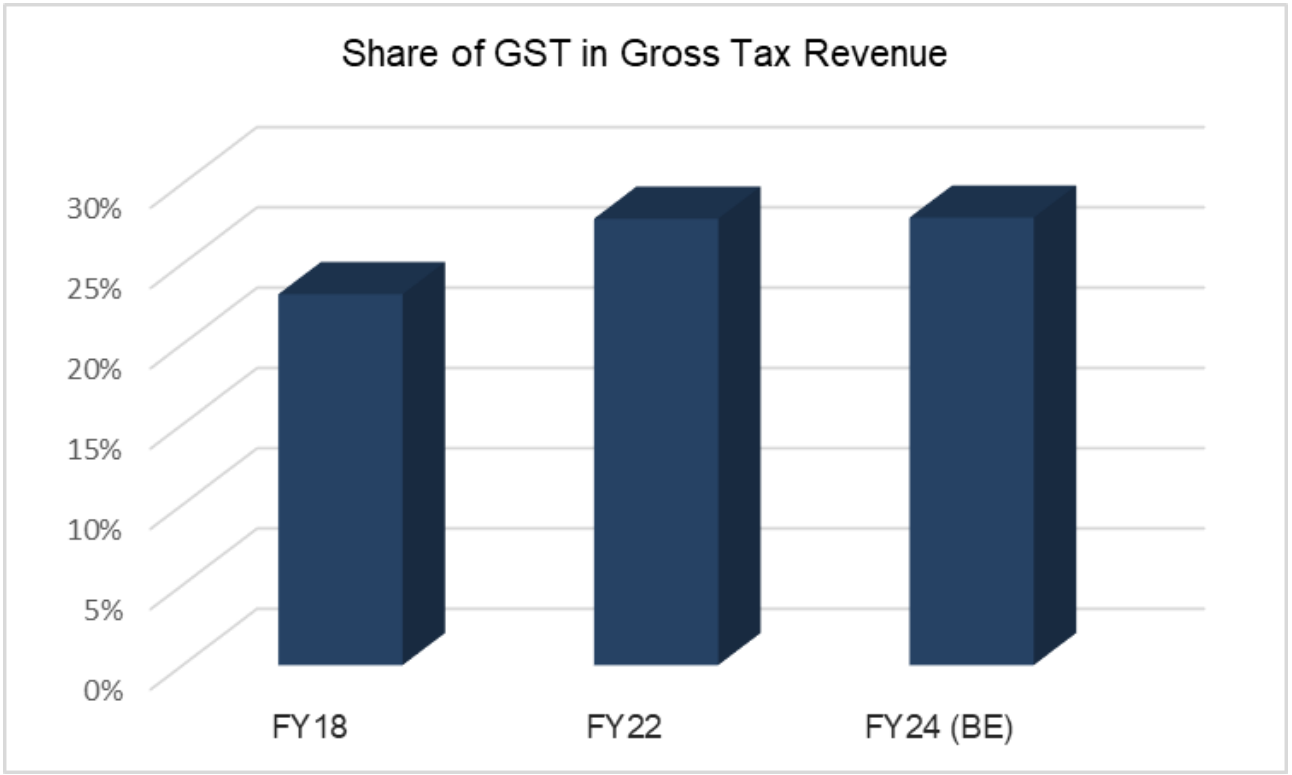

जीएसटी की हकीकत

उच्च जीएसटी संग्रह गरीबों पर बोझ है: हर बार जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छूता है या पार करता है, तो केंद्र जश्न मनाता है, बिना यह महसूस किए कि जीएसटी में वृद्धि प्रतिगामी है क्योंकि दोनों अमीर और गरीब पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। **अप्रैल-दिसंबर (2023-24) के दौरान सकल जीएसटी संग्रह (15 लाख करोड़) इसी वर्ष 2022-23 के दौरान 13.4 लाख करोड़ से 11.7% अधिक था**।

दुनिया भर में जीएसटी दरें: यह भी कहा गया कि जीएसटी पहले से ही 160 देशों में लागू था, इसे सबसे पहले अपनाने वाला फ्रांस था, जिसने 1954 की शुरुआत में जीएसटी की स्थापना की थी, और भारत जीएसटी लागू करने में इतिहास के सही पक्ष पर था। इस तरह के एक्सट्रपलेशन मुश्किल हैं। जो चीज़ एक देश में काम करती है वह दूसरे देश में काम नहीं कर सकती।अमेरिका में जीएसटी नहीं है और मलेशिया ने 2018 में जीएसटी वापस ले लिया। दुनिया भर में जीएसटी दरों की तुलना करने पर, भारत में जीएसटी तंत्र वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक दर है। ऊंची दरें ज्यादातर गरीब वर्गों को प्रभावित करती हैं, कॉरपोरेट्स और अन्य संपन्न वर्गों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं।

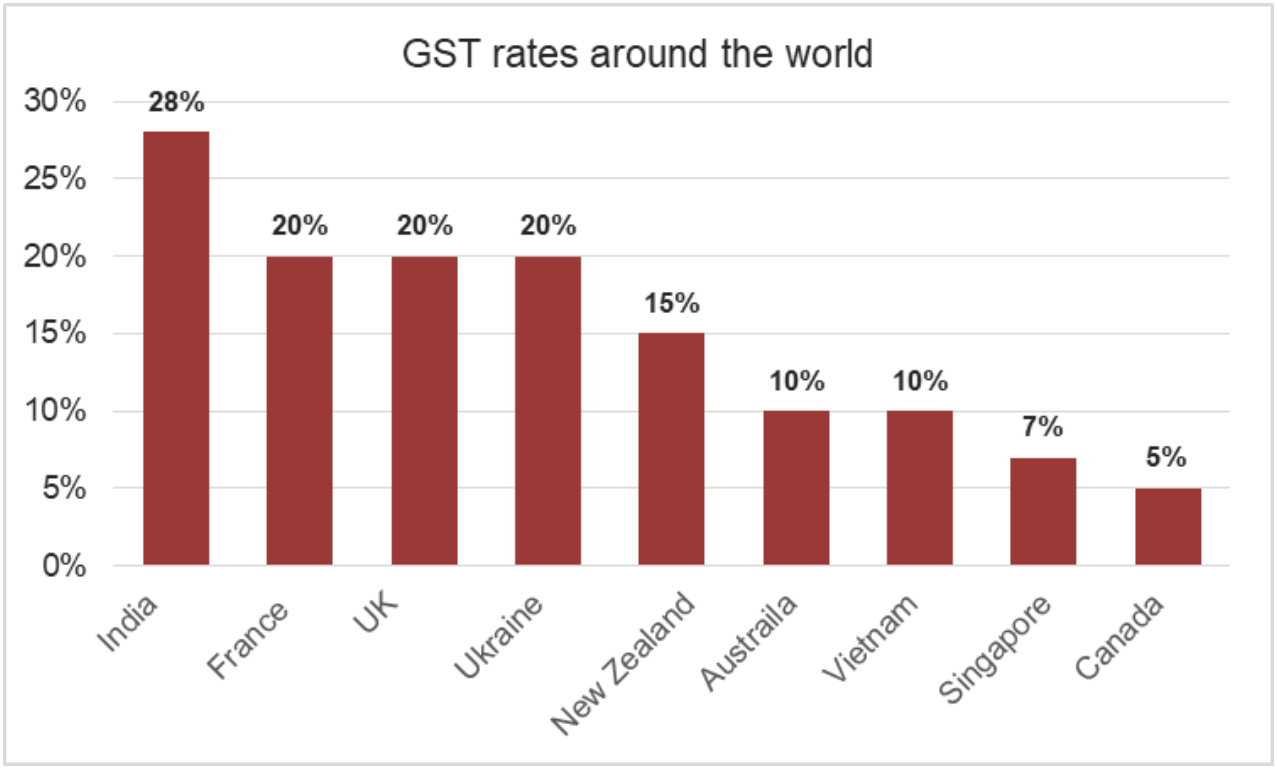

गरीब राज्यों को लाभ नहीं: यह उम्मीद की गई थी कि अंतिम बिंदु कर के रूप में जीएसटी से गरीब, उपभोग करने वाले राज्यों को लाभ होगा। इससे अंतरराज्यीय असमानता कम होने की उम्मीद थी। लेकिन इसके विपरीत हुआ है क्योंकि असंगठित क्षेत्र गरीब राज्यों में केंद्रित है। चूँकि इस क्षेत्र में गिरावट आई है, इससे अमीर राज्यों की तुलना में गरीब राज्यों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जीएसटी की शुरुआत से पहले, 2005-06 से 2015-16 की अवधि में, सभी भारतीय राज्यों के संयुक्त राज्य बजट में औसतन राजस्व अधिशेष था। हालाँकि, 2017 के बाद की अवधि में, जब जीएसटी लागू किया गया था, सभी राज्यों के बजट का औसत राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6 प्रतिशत दर्शाता है।

जीएसटी ने अपनी शुरूआत के बाद से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और मुद्रास्फीति की दर को प्रभावित किया है: ऐसा कहा गया था कि जीएसटी की शुरूआत से अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि होगी और कीमतों के स्तर में कमी आएगी। हालाँकि, डेटा से कुछ और ही पता चलता है। **जीएसटी के बाद अर्थव्यवस्था की विकास दर देश में महामारी आने से पहले 2016 में 8% से गिरकर लगभग 3% हो गई**। आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को 7% से संशोधित कर 6.5% कर दिया है जो कि 2016 में हुई वृद्धि से अभी भी कम है। जीएसटी की शुरूआत से पहले और वर्तमान समय में कीमतों के स्तर की तुलना करने पर, कोई भी वृद्धि की पहचान कर सकता है। **मुद्रास्फीति की दर जो जुलाई 2023 में लगभग 7.44% थी। 2016 में 4.9% (वार्षिक औसत) से बढ़कर 2022-23 में 6.7% हो गई।**

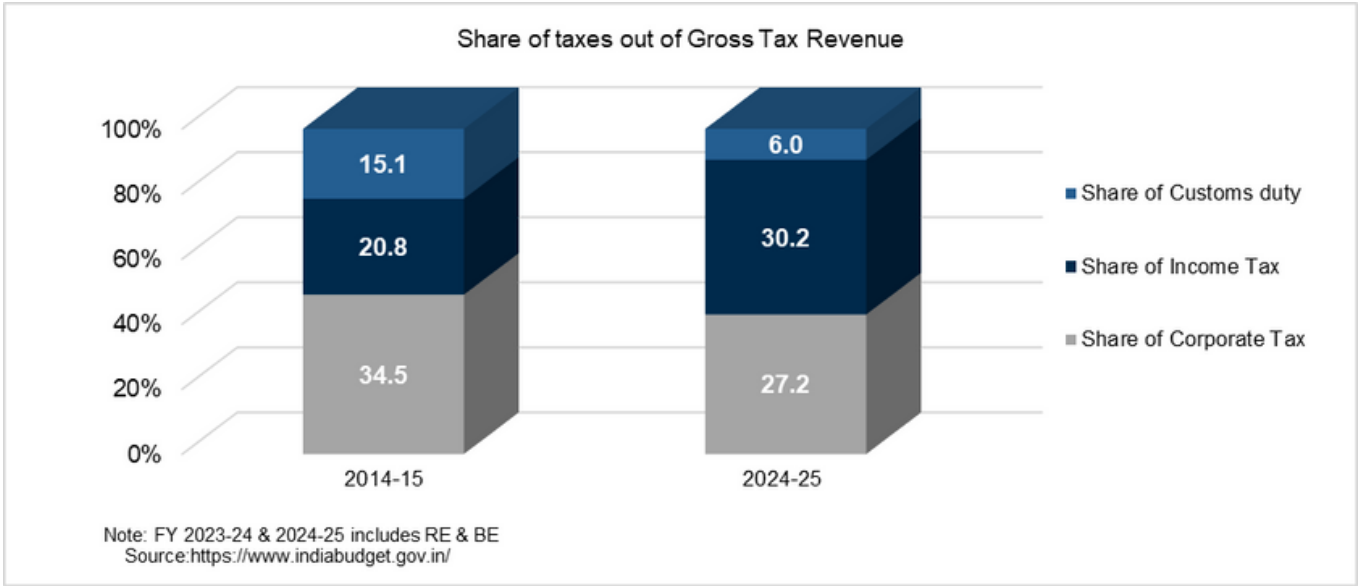

ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में टैक्स का हिस्सा: कॉर्पोरेट कर में कटौती

2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को मौजूदा के लिए 30 प्रतिशत की अधिकतम आधार दर से घटाकर 22 प्रतिशत और नए विनिर्माण के लिए 18 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया (छूट का दावा किए बिना) (वित्त मंत्रालय 2020)

2024-25 के बजट के हालिया अनुमान के अनुसार, आयकर संग्रह 2014-15 में 2.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 11.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है, यानी लगभग 6 गुना की वृद्धि

हालाँकि इसी अवधि के दौरान कॉरपोरेट्स पर लगाया जाने वाला कर केवल 2.5 गुना बढ़कर **4.3 लाख करोड़ से 10.4 लाख करोड़** हो गया। इससे देश के कामकाजी वर्ग के लोगों पर बोझ पड़ा है क्योंकि मोदी सरकार गरीब वर्गों से संसाधनों को स्थानांतरित करके इन बड़े निगमों का वित्तपोषण कर रही है।

बजट के हालिया अनुमान बताते हैं कि सकल कर राजस्व में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा 2014-15 में 34.5% से घटकर 2024-25 में 27.2% हो गया है, दूसरी ओर,आयकर का हिस्सा 20.8% से बढ़कर 30.2% हो गया है। कस्टम ड्यूटी का हिस्सा भी 15.1% से घटकर 6% हो गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान सरकार मध्यम वर्ग पर अधिक निर्भर होने की कोशिश कर रही है और कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा कम कर रही है।

केंद्र, राज्य और टैक्स बास्केट

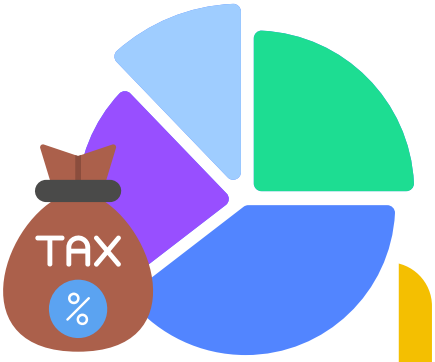

भारी अंतर: वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हिस्सेदारी और राज्यों को हस्तांतरित वास्तविक हिस्सेदारी के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2015-16 में 34.8% से घटकर 2022-23 में 29.6% हो गई, जहां **14वें और 15वें वित्त आयोग में अनुशंसित हिस्सेदारी क्रमश: 42% और 41% थी।**.

राज्यों को कितना नुकसान हो रहा है? 14वें एफसी अवधि के दौरान राज्यों को हस्तांतरित नहीं की गई कुल राशि 1.36 लाख करोड़ रुपये थी और 15वें एफसी के दौरान 3.69 लाख करोड़ रुपये थी। एफसी की सिफारिशों के अनुसार राज्यों की पात्रता और वास्तविक विचलन के बीच का अंतर 13वें एफसी के अंतर से लगभग **3 गुना बढ़ गया** जो लगभग 45,000 करोड़ रुपये था।

सेस ट्रिक: मोदी सरकार के तहत सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2012 में **10.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2011 में 20%** हो गई है। उपकर और अधिभार से प्राप्तियां करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं बल्कि भारत की समेकित निधि के तहत आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाती हैं। तो राज्यों को नुकसान!

हाइलाइट

जीएसटी से गरीबों को नुकसान हो रहा है!!

चूंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जहां कर का बोझ खरीदार और विक्रेता दोनों द्वारा साझा किया जाता है, कर संग्रह में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि होगी। चूँकि गरीब वर्ग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष कर चुकाने में खर्च करता है। **जीएसटी आबादी के गरीब वर्गों को दंडित करता है**।

आवश्यक इनपुट सहित सभी वस्तुओं पर जीएसटी जैसी एक समान कर दर ने उत्पादन के हर चरण में लागत बढ़ाकर कीमतों को बढ़ा दिया है।

दावों के विपरीत, **आउटपुट उत्पादन में गिरावट** आई है क्योंकि **छोटे व्यवसाय बंद** हो गए हैं, सामना करने में असमर्थ हैं, जबकि बड़े व्यवसायों ने अपनी क्षमताएं बढ़ा ली हैं और कार्यभार संभाल लिया है।

जैसा कि जीएसटी में बताया गया है, संगठित क्षेत्र में वृद्धि असंगठित क्षेत्र की कीमत पर है। उदाहरण के लिए, **ई-कॉमर्स (संगठित क्षेत्र में) असंगठित क्षेत्र के व्यापार की कीमत पर बढ़ रहा है**।

क्या आयकर डेटा वास्तव में कम होती असमानता दिखाता है?

आयकर डेटा क्या दर्शाता है?

भले ही आयकर डेटा असमानता में कमी दिखाता है, वह केवल रिटर्न दाखिल करने वालों से है जो आबादी का केवल 5.5% हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण जनसंख्या में वास्तविक असमानता के बारे में नहीं बता सकता। इसकी पुष्टि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भी की थी कि 'भारत में केवल 1 प्रतिशत आबादी ही प्रत्यक्ष करदाता है' (लोकसभा 2020)।

टैक्स चोरी और अमीरों के लिए कर राहत

क्रेडिट सुइस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 और 2019 में भारत में 7.25 लाख और 9.12 लाख डॉलर करोड़पति (भौतिक और वित्तीय संपत्ति) थे। यह मानते हुए कि उनकी वार्षिक आय उनकी संपत्ति का सिर्फ 10 प्रतिशत थी, इसका मतलब 70 लाख रुपये होगा। लेकिन निर्धारण वर्ष 2018-19 के कर डेटा से पता चलता है कि केवल 29,002 व्यक्तियों ने 50 लाख रुपये से अधिक की आय घोषित की - जो उस समय के आसपास 7.25-9.12 लाख डॉलर करोड़पति से काफी कम थी। यह बड़ा अंतर बड़े पैमाने पर कर चोरी और खराब कर प्रणाली का संकेत देता है।

2023-24 के बजट में सुपर रिच (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों) को एक और कर राहत का प्रस्ताव है। आय पर अधिकतम अधिभार 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, इस प्रकार अधिकतम आयकर दर 43 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है।

संपत्ति कर के बारे में क्या हम सोच सकते है?

भारत में 2015 में संपत्ति कर समाप्त कर दिया गया था।
इसके उन्मूलन से ठीक पहले, 30 लाख रुपये से अधिक की कुल संपत्ति पर 1% की समान दर से संपत्ति कर लगाया जाता था। जब यह लागू था तब भी इसे कभी ठीक से लागू नहीं किया गया। 2015-16 में इसने महज 1,079 करोड़ रुपये कमाए।

भारत को किस प्रकार का संपत्ति कर अपनाना चाहिए?

एस सुब्रमण्यम (2020) ने अनुमान लगाया कि भारत के सबसे धनी 953 परिवारों पर **4% का COVID** संपत्ति कर सकल घरेलू उत्पाद के 1% के बराबर राजस्व उत्पन्न कर सकता है, और यह महामारी के बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज से अधिक था।

प्रोफेसर प्रभात पटनायक (2020) का अनुमान है कि देश में **शीर्ष 1% पर 2% का संपत्ति कर राजस्व के रूप में 8 लाख करोड़ रुपये** लाएगा। **33% का विरासत कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये** और जोड़ सकता है।

प्रोफेसर ईशान आनंद और अंजना थम्पी ने अतिरिक्त राजस्व के कुछ अनुमान प्रदान किए जो सबसे धनी भारतीयों पर फ्लैट कर और प्रगतिशील धन कर लागू करने पर उत्पन्न हो सकते हैं:

यदि देश के **सबसे धनी 1,007 परिवारों को 2% की एक फ्लैट संपत्ति कर** दर के साथ लक्षित किया जाता, तो **2021 में उत्पन्न कुल कर राजस्व 1.84 लाख करोड़ रुपये** होता।

सीमांत रूप से, व्यक्ति की **कुल संपत्ति के आधार पर 2% से 6% तक की वृद्धिशील संपत्ति कर दरों से 2021 में 2.76 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व उत्पन्न होगा**।

इसका उपयोग अधिकार आधारित कल्याण योजनाओं के एक बड़े हिस्से की गारंटी और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर पर्याप्त सार्वजनिक खर्च सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों और मध्यम वर्ग पर नहीं!

अन्य रिपोर्ट कार्ड नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:
https://bit.ly/BSofadecade

https://www.fanindia.net Financial Accountability Network
@_FANIndia Financial Accountability Network India - FAN India fanindia.info@gmail.com